भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या 579
06 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

**जलवायु परिवर्तन का प्रभाव**

**579. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मत्स्यपालन और जलीय कृषि की सततता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर कोई अध्ययन किया है;
(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन का ब्यौरा क्या है;
(ग) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से प्रभावित मछुआरा समुदाय की अनुमानित संख्या कितनी है; और
(घ) सरकार द्वारा विशेष रूप से कर्नाटक में मछुआरा समुदाय की आजीविका की रक्षा के लिए बनाई गई रणनीतियों और उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री परशोत्तम रूपाला)**

(क) से (ग): मात्स्यिकी और जलीय कृषि के स्थायित्व के उद्देश्य से (ससटेनेबिलीटी) जलवायु अनुकूल रणनीतियां विकसित करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारत सरकार के तत्वावधान में मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिए नियमित रूप से अनुसंधान कर रहे हैं । आईसीएआर संस्थानों द्वारा "नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए)" के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययनों में आर्द्रभूमि मात्स्यिकी की संवेदनशीलता का आकलन, भारत भर में प्रमुख नदी घाटियों में जलवायु प्रवृत्ति विश्लेषण, मत्स्य वितरण संबंधी प्रभाव, पकड़ी गई मछलियों के प्रकार, उपज आदि शामिल हैं । समुद्री मात्स्यिकी के संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग पर अध्ययन, जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के ध्यानार्थ फिश कैच और मेरीकल्चर उत्पादन पर अनुमान, समुद्री मात्स्यिकी के जोखिम और वलनेरेबिलिटी का आकलन, आर्द्रभूमि मानचित्रण, कार्बन फूटप्रिंट, ब्लू कार्बन क्षमता, महासागर अम्लीकरण, जलवायु परिवर्तन के प्रति कैप्चर तथा कल्चर प्रजातियों की प्रतिक्रिया और जलवायु परिवर्तन के आलोक में एडेपटिव मेनेजमेंट एनआईसीआरए परियोजना के अंतर्गत किया जाता है । जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मछुआरों की तैयारियों को सुदृढ़ करने और एडेप्ट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में जलवायु अभियान और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं ।

(घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने *प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना* (पीएमएमएसवाई) के तहत विगत दो वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष में कर्नाटक सरकार को 1004.12 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है । यह निवेश वार्षिक रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान 20,414 पारंपरिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े मछुआरों के परिवारों को आजीविका और पोषण सहायता प्रदान करने सहित राज्य में मछुआरों के समग्र विकास और कल्याण के लिए मात्स्यिकी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए है ।

*****